राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चार राज्यों के चुनाव में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों में शामिल सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान से पहले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सोमवार को सचिन पायलट ने नोएडा में कांग्रेसी उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस को जीत दिलाने की अपील की।

उपलब्धियों की बुकलेट नहीं छापने पर विधायकों पर नाराज हुए मुख्यमंत्री गहलोत

चिंतन शिविर को लेकर बोले सचिन पायलट-यह संवाद का अच्छा तरीका है

जयपुर, 7 फरवरी (का.प्र.)। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों का तीन दिवसीय चिंतन शिविर होटल लीला पैलेस में चल रहा है। चिंतन शिविर को लेकर कितनी गंभीरता है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि शिविर के पहले दिन दोपहर में ही विधायक पहुंच गए, लेकिन देर शाम तक ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, ना प्रभारी अजय माकन पहुंचे। ऐसे में पहले दिन चिंतन शिविर में पहुंचे विधायकों ने एक दूसरे के साथ में बातचीत करके समय काटा।

दूसरे दिन सुबह विधायक दल की बैठक हुई इस बैठक में सामने की ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात के प्रभारी डॉ रघु शर्मा और मंत्री डॉ बी डी कल्ला बैठे। वही बाकी सभी विधायकों को सामने बिठाया गया। दूसरे दिन विधायक दल की बैठक में रीट का मुद्दा ही छाया और अधिकांश विधायकों ने मुख्यमंत्री के पूछे जाने पर रीट की परीक्षा को रद्द करने की बात ही कही। इसके अलावा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों पर भी नाराजगी प्रकट कर दी दरअसल यह नाराजगी इस बात पर थी कि, सभी विधायकों को पहले ही कहा जा चुका कि, वे अपने क्षेत्र में हुए काम की बुकलेट छपायें और उसे बंटवाए,ताकि यह पता चल सके कि उनके क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किए हैं। अभी तक किसी भी विधायक ने यह बुकलेट नहीं छपाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने किए हुए काम ही नहीं बताओगे तो जनता को पता कैसे चलेगा। इसी कड़ी में चिंतन शिविर के दूसरे दिन शाम को जिलेवार विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याएं जानने का प्रयास किया गया। बैठक के बाद में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अपने विधायकों के साथ संवाद का यह अच्छा तरीका है। बजट से पहले सभी विधायकों से उनके सुझाव लेना और राय जानना अच्छी प्रक्रिया है।

चिंतन शिविर में विधायकों से संगठन के बारे में भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। इसी के साथ विधायकों को बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के बारे में भी रणनीति समझाई जाएगी।

हिन्दुस्तान ज़िंक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर्यावरण मानकों के उल्लंघन तथा बड़े पैमाने पर नुकसान होने की बात कही गई थी। ट्रिब्यूनल प्रमुख आदर्श कुमार गोयल, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज रह चुके हैं, की अध्यक्षता वाली बैंच ने हिन्दुस्तान ज़िंक को आदेश दिया कि, वह तीन महीने के अंदर भीलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जुर्माना-राशि जमा कराये ताकि इकोलॉजिकल रीहैबिलिटेशन तथा रैस्टोरेशन के उपचारक उपायों का खर्च वहन किया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने कुओं, गड्ढों, कृषि-उत्पादों मवेशियों को नुकसान पहुँचाने, भूगर्भजल के संदूषण (कन्टैमिनेशन) तथा भू-अवक्रमण (डिग्रडेशन) के आरोप लगाये थे तथा इस बात के सुस्पष्ट प्रमाण दिये थे कि, यह नुकसान इन औद्योगिक गतिविधियों के कारण ही हुआ है।

रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द किया गया

कैबिनेट की बैठक के बाद मु.मंत्री ने किया ऐलान, अब लेवल 1 और 2 को मिलाकर कुल 62000 पदों पर होगी भर्ती

- **सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर सरकार और मंत्री वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन एसओजी के फंदे में जब सरकार के नजदीकी लोग फंसे तो गलफांस बनी यही परीक्षा।**
- **अभी भी मंत्री सुभाष गर्ग और राजीव गांधी स्टडी सर्किल को लेकर खड़े हैं सवाल, एसओजी की जांच जारी रहेगी।**

जयपुर, 7 फरवरी (का.प्र.)। प्रदेश की गहलोत सरकार ने गले की फांस बनी रीट लेवल 2 परीक्षा को रद्द कर दिया है। वही लेवल वन को यथावत रखा जाएगा। अब दोनों लेवल को मिलाकर कुल 62000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया गया। इससे पहले विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों से इस संबंध में सुझाव लिए गए थे और अधिकांश विधायकों ने रीट रद्द करने की बात सरकार के सामने रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रीट लेवल-2 के एग्जाम को निरस्त किया जाता है।

इससे पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान एलिजबिलिटी एग्जामिनेशन फोर टीचर्स (रीट) 2021 को लेकर वाहवाही लूट रही थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा सरकार के अधिकांश मंत्री और विधायक इस परीक्षा कराने को लेकर वाहवाही लूट रहे थे और लगातार कह रहे थे कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। हालांकि परीक्षा संपन्न होने के साथ ही इसमें गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर लगातार खुलासे हो रहे थे और फिर जब बोर्ड अध्यक्ष और परीक्षा समन्वयकों सहित अन्य पर आरोप लगने लगे और भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे सीएमओ से जुड़े अधिकारी और मंत्री तक के इस मामले में जुड़े होने के आरोप लगाए तो सरकार बचाव की मुद्रा आ गई। इधर एसओजी के हाथ में मामला आने के बाद कई स्तर पर गिरफ्तारियां भी हुई।

दरअसल रीट पेपर लीक मामले को लेकर सबसे ज्यादा आरोप राज्य के मंत्री सुभाष गर्ग पर लग रहे हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली और परीक्षा समन्वयक प्रदीप पाराशर जिसे एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अन्य जिलों में समन्वयक बनाए गए लोग राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए हैं और जिसके कर्ता-धर्ता सुभाष गर्ग हैं। हालांकि सुभाष गर्ग पर लग रहे आरोपों के बावजूद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं नजर आए, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधे आरोप नहीं होने और मंत्री पद छोड़ने के बावजूद वे सफाई देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहे।

दरअसल रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर आई शिकायतों के बाद गहलोत सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी ने भी परीक्षा में हुई धांधली पर मुहर लगा दी है। एसओजी की ओर से जब यह साफ हो गया कि एक गिरोह के जरिये पेपर लीक कर बाजार में बेचा गया। उसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब रीट परीक्षा में योग्य घोषित हुए 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सोमवार को प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रीट लेवल -2 परीक्षा रद्द करने तथा 62 हजार पदों के लिए यह परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की।

अशोक गहलोत ने कहा कि, अब शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दो एग्जाम होंगे। रीट केवल एलिजिबिलिटी टैस्ट रहेगा। उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए टैस्ट देना होगा। सरकार इसके लिए नियमों में संशोधन करेगी। इसी के साथ रीट पेपर लीक प्रकरण की जांच को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि, रीट मामले की जांच एसओजी ही करेगी। हालांकि रीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को देने की मांग भाजपा कर रही है। इस संबंध में भाजपा की ओर से विरोध-प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

गहलोत ने कहा था कि आपराधिक लापरवाही बड़ा जुल्म होता है, हमने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त किया है और सचिव को सस्पेंड किया है। कई कार्मिकों को भी सस्पेंड किया गया है। जांच आगे बढ़ रही है और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि, रीट परीक्षा में एक भी आरोप साबित कर दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मेरे परिवार के 13 लोगों ने परीक्षा दी, लेकिन सब फेल हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की आपस की लड़ाई में 20 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किरोड़ी मीणा, सतीश पूनिया सिर्फ दिल्ली वाले नेताओं को खुश करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि, हमने जांच के लिए एसओजी को फ्री हैंड कर दिया है। बीजेपी को एसओजी जांच का इंतजार करना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि, बीजेपी के नेता कोयले की तरह काले हैं, वो हमारी सफेदी पर क्या आरोप लगाएंगे?

'कश्मीर का गलत चित्रण हुआ'

मॉस्को, 7 फरवरी। रूस ने अपनी उन मीडिया रिपोर्ट्स को सीधे तौर पर नकार दिया है, जिनमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने इस विवाद पर बयान जारी कर कहा कि कश्मीर पर कोई भी बात भारत-पाकिस्तान का आपसी मसला है।

पुतिन सरकार का यह बयान रेडफिश डिजिटल मीडिया की ओर से किए गए उस ट्वीट के बाद आया है,

- **रशियन मीडिया में कश्मीर पर आई खबरों को पुतिन सरकार ने नकारा।**

जिसमें उसने कश्मीर पर बनाई एक डॉक्युमेंट्री की झलक दिखाई थी और कश्मीर की फलस्तीन से तुलना कर दी थी। ट्विटर पर रेडफिश डिजिटल मीडिया को रूस की सरकारी मीडिया बताया गया है। अपनी वेबसाइट पर रेडफिश खुद को कई अवॉर्ड जीतने वाला डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बताता है।

इसी डॉक्युमेंट्री को लेकर उठे विवाद के बाद रूसी दूतावास ने बयान जारी किया है।

वैक्सीन लगाने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पैन कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा सूर्य कान्त की बैंच ने तदनुसार पुणे जिले के कोठरूड़ नामक कस्बे के सिद्धार्थ शंकर शर्मा की पी.आई.एल. को निपटा दिया। बैंच ने पी.आई.एल. को लेकर केन्द्र को नोटिस जारी कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "केन्द्र के वकील का कहना है कि, करीब 87 लाख ऐसे लोग, जिनके पास पहचान पत्र नहीं थे, को टीका लगा दिया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत भी शपथ पत्र पर की गई है कि, उसे आधार कार्ड प्रस्तुत न करने के कारण टीका लगाने से मना कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा कि, संबंधित प्राइवेट वैक्सिनेशन सैन्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाये, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा बैध पासपोर्ट आई.डी. प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उसे टीका लगाने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता की शिकायत पर पूरा ध्यान दिया गया था। "अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा, "सभी संबंधित अधिकारियों को सरकार की नीति के अनुरूप कार्य करना चाहिए।"

जे.एन.यू. की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में जन्मी शांतिश्री वर्ष 1988 से ही शिक्षण कार्य करती रही हैं। वह कई जाने-माने संगठनों से संबद्ध हैं, जैसे कि इण्डियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन स्टडीज़, मण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, द अमेरिकन स्टडीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद व इण्डियन सैक्युलर सोसायटी और ऑल इण्डिया पॉलिटिक्ल साइंस एसोसिएशन। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनमें-"पार्लियामैंट एण्ड फॉरैन पॉलिसी इन इण्डिया" (1990) तथा "रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरमैन्टल गवर्नेंस इन एशिया-एथिक्स एण्ड पॉलिसी" (2003) शामिल हैं। वे जे.एन.यू. के लिए नई नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पी.एच.डी. और एम. फिल की उपाधियां यहीं से प्राप्त की थीं और वर्ष 1985-86 में वह जे.एन.यू. के झेलम हॉस्टल की प्रैसीडैंट भी रह चुकी हैं।

अगर आप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संख्या बढ़ सके, जो इस समय बहुत कम, 10 लाख के आसपास है। इनमें 2.5 उत्तर प्रदेश के खरीदार तथा 1.26 लाख दिल्ली के खरीदार शामिल हैं। कारों और स्कूटरों में काम आने वाली 81 प्रतिशत लीथियम बैटरियाँ भारत में ही बनती हैं, जबकि कई संस्थान इन बैटरियों की कीमतें कम करने पर शोध कर रहे हैं। यह बात मंत्रालय के उन अधिकारियों ने कही है, जो इन संस्थानों के सम्पर्क में हैं।

यूरोप में भारी "डिप्लोमैटिक" गतिविधि...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुतिन कुछ नहीं कर पाएंगे।

राष्ट्रपति पुतिन अपनी लाज बचाने का कोई फॉर्मूला बड़ी सक्रियता से तलाश रहे हैं, ताकि, युद्ध शुरु करने और अपने देश व अपनी मित्र मण्डली के सहयोगियों के विरूद्ध, कठोर प्रतिबंध लगने का दोष उनके मत्थे ना मढ़ जाए।

पुतिन का अंतिम लक्ष्य, उनके खिलाफ बने पश्चिमी देशों के संयुक्त गठजोड़ को विभाजित करना है, जिसने वैश्विक कूटनीतिक व्यवस्था में उन्हें पूर्णतया अलग-थलग कर दिया है। वे उस समय काफी आवेश में आ गए थे जब रूस को जी-8 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जी-8 विश्व के विकसित एवं सर्वाधिक सशक्त देशों का संगठन है, जो दुनिया के समक्ष मौजूद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियमित रूप से अपने विचार व्यक्त करता है।

जी-8 से रूस को बाहर किए जाने का दर्द पुतिन को अब भी सालता है, क्योंकि इसका मतलब था दुनिया के शीर्ष कूटनीतिक मंचों से उनकी उपस्थिति खत्म होना। रूस को बड़ी व्याकुलता से जी-8 व्यवस्था का हिस्सा बनने की इच्छा है।

मैक्रॉं-पुतिन वार्ताओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन को प्रभावित करने में मैक्रॉं की क्षमता अन्य के मुकाबले ज्यादा है। अन्य की तुलना में उनके पास दो बड़े एडवांटेज है। पहली तो यह कि, पुतिन को लेकर मैक्रॉं पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं।

उन्होंने उनके साथ पिछले दो महीनों में कम से कम पांच बार टेलीफोन पर बातचीत की है। इसके विपरीत अन्य नेताओं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पुतिन से सिर्फ दो बार ही टेलीफोन पर बातचीत की है।

दूसरी यह कि, फ्रांस के राष्ट्रपति का फिलहाल यूरोप यूनियन (ई.यू.) में दबदबा है, क्योंकि फ्रांस वर्तमान में पूरे छह माह के लिए इसका अध्यक्ष है और रूस के संबंध में ई.यू. के किसी एकीकृत रूख की रूपरेखा बनाने में मैक्रॉं प्रभावशाली स्थिति में हैं।

रूसी मनोस्थिति पर फ्रांस की एक दीर्घ ऐतिहासिक पकड़ रही है। आधुनिक रूस के निर्माता पीटर द ग्रेट रूस को फ्रांस के ढांचे में ढालना चाहते थे। वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति के कुलीन वर्ग की भाषा एक तरह से फ्रैंच ही थी।

रूसी बुद्धिजीवियों और लेखकों, सभी को सौन्दर्य प्रसाधनों का आनंद लेने और फ्रैंच मनोभावों को आत्मसात करने के लिए पेरिस आना पड़ता था। तुर्गनेव से लेकर चैकॉव्स्की और टॉल्सटॉय से लेकर बोल्शोई थिएटर, सभी पश्चिमी आचार-विचार और आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करते थे।

रूस बड़ी अधीरता से यह चाहता है कि, यूरोप के कुलीन लोग उसे एक यूरोपीय शक्ति के रूप में मान्यता दें। पुतिन रूस के लिए यह पहचान व सम्मान चाहते हैं।

ममता बनर्जी प्रचार करने लखनऊ पहुंची

कोलकाता, 7 फरवरी। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (एस.पी.) के पक्ष में प्रचार के लिए सोमवार को लखनऊ

- **ममता बनर्जी मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ जॉइन्ट प्रैस कॉन्फ्रेंस लेंगी।**

पहुंच गईं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। ममता बनर्जी मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता करेंगी। वह वाराणसी भी जाएंगी। वहां वह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी।

कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण किया

कुछ दिनों पहले मीडिया पर, बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा को धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था। उसी मामले में 50,000 का इनामी बदमाश जगन गुर्जर कई दिनों से फरार चल रहा था

- **आज डकैत जगन गुर्जर ने करौली पुलिस और डीएसटी टीम के सामने मासलपुर के जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया।**
- **पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र इंदौरिया ने बताया कि डकैत जगन के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं।**

करौली, 7 फरवरी (निस)। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने करौली पुलिस और डीएसटी (जिला पुलिस) टीम के सामने सोमवार को मासलपुर के जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया।

कई दिनों पहले मीडिया पर बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा को धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था। उसी मामले में 50000 का इनामी बदमाश और जिला धौलपुर के विभिन्न प्रकरणों में वांछित कुख्यात डकैत जगन गुर्जर पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन आज डकैत जगन गुर्जर ने करौली पुलिस और डीएसटी टीम के सामने मासलपुर के जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया। कार्रवाई में राजेश कांस्टेबल थाना नादौती, कुंवर सिंह कांस्टेबल थाना नादौती व जिला भरतपुर का पुलिस बल शामिल था।

पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौरिया ने बताया कि, डकैत जगन के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में जगन गुर्जर को पकड़ने के लिए आईजी के निर्देशन में जिला धौलपुर एवं करौली पुलिस की विभिन्न टीमें बनाई गई थी। उसी के मद्देनजर आज मासलपुर के जंगलों की सूचना मिलते ही डीएसटी टीम के कांस्टेबल राजेश कुमार कॉन्स्टेबल कुमार सिंह और कॉन्स्टेबल पुनीत ने कड़ी मशक्कत करके कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की।

डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दलित समुदाय और निर्धन वर्ग में हजारों की संख्या में लोग डेरों के अनुयायी हैं तथा इसलिए माना जा रहा है कि, राम रहीम चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की एकाएक रिहाई पर आपत्ति जताई है। राम रहीम के नाम से मशहूर इस बाबा के अनुयायी पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में हैं, और ज्ञातव्य है कि, पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। राम रहीम को करीब दो दशकों से पंजाब और हरियाणा के राजनेताओं और राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था क्योंकि चुनावों में उसके अनुयायियों पर उसका प्रभाव काफी महत्व रखता था।

2014 के लोक सभा चुनावों तथा उसके बाद हुये हरियाणा विधानसभा चुनावों में, डेरा सच्चा सौदा तथा पंजाब के भटिंडा जिले के सलाबतपुर के एक प्रतिष्ठित पंथ ने लोगों से भाजपा को वोट

- **डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि, देश में उनके 6 करोड़ अनुयायी हैं, जिसमें से 40 लाख तो केवल पंजाब में ही हैं।**
- **2017 में इस डेरे ने अकाली दल-भाजपा को वोट देने का "आदेश" दिया था, विधानसभा चुनाव में, पर यह गठबंधन चुनाव हारा था। लेकिन, 2012 व 2007 में कांग्रेस को वोट देने का "हुक्म" जारी किया था।**

देने की सार्वजनिक अपील की थी। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में, इस पंथ ने शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन को अपना समर्थन-सहयोग दिया था, लेकिन गठबंधन कांग्रेस से पराजित हो गया था। इस पंथ का दावा है कि, पूरे भारत में उसके 6 करोड़ अनुयायी हैं जिनमें से 40 लाख अकेले पंजाब में हैं। तथापि, 2012 व 2007 के विधानसभा चुनावों में इस पंथ ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था।

डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी, यदि वो सौदा प्रमुख के फरमान को मानते हैं, तो मालवा क्षेत्र की 35-40 सीटों के परिणाम प्रभावित करेंगे। ज्ञातव्य है कि, मालवा क्षेत्र, पंजाब का विशालतम राजनैतिक क्षेत्र है, जिसमें 69 विधानसभा क्षेत्र समाहित हैं, जबकि राज्य में कुल 117 विधानसभा सीट हैं। राम रहीम के पूरे पंजाब में 84 परिसर हैं, जिन्हें "सत्संग घर" कहा जाता है, यहाँ पर राम रहीम का आदेश सर्वोपरि माना जाता है।

बलात्कार और हत्या के केसों में दोषी पाए जाने के बाद राम-रहीम वर्ष 2017 से ही हरियाणा की हाई सिक्यूरिटी सुनारिया जेल में बंद है। बलात्कारों और हत्याओं के जुर्म में उन्हें अगस्त 2017 में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला और सिरसा में हिंसा फैल गई थी, जिसमें 41 जने मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे। जनवरी 2019 में पंचकुला की एक विशेष सी.बी.आई. कोर्ट ने पत्रकार राम चन्दर छत्रपति की करीब 16 वर्ष पहले हुई हत्या के जुर्म में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

यह चौथी बार है कि, राम रहीम जेल से बाहर हैं। पहले भी उन्हें विभिन्न कारणों से कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया गया था, जिसमें अपनी बीमार मां से मिलने की बात भी शामिल है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि, राम-रहीम की रिहाई को किसी राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए, क्योंकि उन्हें जेल नियमावली के हिसाब से पैरोल मंजूर की गई है और कैदियों को पैरोल या गैर हाजिर रहने की अनुमति प्रदान किए जाने से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि, कानूनन कोई भी दोषी अपनी दोषसिद्धि के तीन वर्ष बाद पैरोल या गैरहाजिरी की छूट लेने की पात्रता रखता है। राम-रहीम को मिली गैर हाजिर रहने की छूट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) ने हरियाणा सरकार से कहा है कि, हत्याओं के जिम्मेवार किसी अपराधी को जेल से रिहा करने से बाज आए। एस.जी.पी.सी. का काम गुरुद्वारों का प्रबंधन करना है।

करौली क्षेत्र के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर (फोटो में नीचे बैठा हुआ) को पुलिस की जॉइन्ट ऑपरेशन टीम ने सोमवार को मासलपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया। पचास हजार के ईनामी जगन गुर्जर के खिलाफ अपराध के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908